पंचायतों के निदेशक की शक्तियों के साथ सम्मानित किया गया, 10 मई, 1988 को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायतों को दिनांकित आदेशों के तहत उनके आदेश के खिलाफ एक अपील थी। अपीलीय आदेश, एनेक्स्योर पी -4, इस प्रकार क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास में पारित किया गया था।

(6) सरकार के सचिव, पंजाब के सचिव, ने भी निर्देशक की शक्तियों को भी सम्मानित किया है, और संयुक्त सचिव को संयुक्त निदेशक की शक्तियों से सम्मानित किया गया है, और इसलिए, एक अपील नहीं कर सकती है। झूठ, एक बुनियादी गिरावट से पीड़ित है, एक अधिकारी के लिए एक से अधिक शक्तियों के साथ सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन बिंदु यह उठता है कि उसे एक समय में यह पता होना चाहिए कि वह किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और क्या वह ऐसा करने के लिए सक्षम था या नहीं। श्री पी। राम अपील का निपटान करते हुए निश्चित रूप से सचेत थे कि वह सरकार, पंजाब, ग्रामीण विकास और पंचायतों के संयुक्त सचिव की शक्तियों को समाप्त कर रहे थे, और वह संयुक्त द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपील में बैठे थे निदेशक, पंचायत, निर्देशक, पंचायतों की शक्तियों का उपयोग करते हुए। संयुक्त सचिव, सरकार, पंजाब के अपीलीय समारोह को संयुक्त निदेशक, पंचायतों के साथ एक समन्वय समारोह नहीं कहा जा सकता है, इस बात पर कि संयुक्त निदेशक भी निदेशक या संयुक्त निदेशक, पंचायतों की शक्तियों के साथ निहित था। इससे बचने की आवश्यकता है कि एक आदमी इस स्वयं के आदेश के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकता है या यह कि एक अधिकारी के आदेश के खिलाफ अधिकार क्षेत्र में समन्वय करता है। हम इस मामले में इस तरह के कुछ भी नहीं पाते हैं, यहां तक कि इसके यांत्रिकी की बारीकी से जांच करते हैं।

(7) किसी अन्य बिंदु से आग्रह नहीं किया गया है।

(8) याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम याचिका को लिमाइन में खारिज कर देते हैं।

आर। एन। आर।

जज एम एम पंचही और अमरजीत चौधरी

रविंदर, -पुटिशनर।

बनाम

डिप्टी कमिश्नर, मोहिंदेरगढ़ और अन्य,- उत्तरदाताओं।

1987 के सिविल रिट याचिका संख्या 7408

2 अगस्त, 1988।

हेल्ड, कि हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियमों के नियम 75 के उप-नियम (1) में तनाव, 1978 सीमा की अवधि के भीतर याचिका की प्रस्तुति पर है। एक याचिका जो सीमा की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, वह उतनी ही अच्छी है जितनी कि एक याचिका के रूप में उपायुक्त के हाथों में नहीं है और यदि ऐसा है, तो उसके लिए राज्य सरकार के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। यह केवल एक प्रस्तुत याचिका है, जिसमें नियम 75 के उप-नियम (1) में वर्णित प्रकार के विवरण का अभाव है, जो कि किसी भी दुर्बलता के मामले में राज्य गो-वर्जन को भेजे जाने के लिए वारंट होगा। तात्कालिक मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ है। इस प्रकार डिप्टी कॉमिस का आदेश- सियोनर ने याचिकाकर्ता की याचिकाकर्ता की याचिका का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया- tion पूरी तरह से सही था।

(Para 1)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत नागरिक रिट याचिका प्रार्थना करते हैं:-

(ए) एक उपयुक्त रिट, ऑर्डर या दिशा को जारी किया जा सकता है- ऑर्डर एनेक्स्योर पी/3 को कम करने के लिए एड और उत्तरदाताओं के नंबर 1 और 2 को आगे मनोरंजन के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और मेरिट-चुनावी याचिका-एनेक्स्योर पी। २ पर निर्णय लिया गया ।

(बी) नगरपालिका समिति का रिकॉर्ड, के लिए बुलाया जाना चाहिए; (c) अनुलग्नक P/2 और P/3 की प्रमाणित प्रतियां कृपया के साथ भेज दी जा सकती हैं।

(घ) अग्रिम सूचना पर उत्तरदाताओं की सेवा के साथ भेजा जाना चाहिए;

(ई) रिट याचिका को लागतों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के लिए आर। ए। यादव, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं 1 और 2 के लिए एस। एस। अहलावत, एडवोकेट, डी.ए.जी., हरियाणा।

एम। एल। सैनी, वकील, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

प्रलय

जज एम एम पंचही, (ओरल)

30 अगस्त, 1987 को हुए एक नगरपालिका चुनाव को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता ने 21 सितंबर, 1987 को डिप्टी कमिश्नर के सामने एक चुनावी याचिका प्रस्तुत की। डिप्टी कॉम-मिशनर ने इस आधार पर प्रस्तुति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह इस आधार पर है।

सीमा द्वारा रोक दिया गया था, जो हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियमों, 1978 के नियम 75 के तहत प्रिस्क्राइब-एड के रूप में 14 दिनों से परे है। 30 दिनों से अधिक अगर वहाँ थे, उनकी राय में, इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त आधार। लगाए गए ऑर्डर एनेक्स्योर पी -3 के आधार पर उन्होंने कहा कि सीमा

की अवधि का विस्तार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे क्योंकि याचिकाकर्ता इस बीच में docu- ments की प्रमाणित प्रतियों की खरीद में व्यस्त था। यह ट्रांसपायर करता है कि याचिकाकर्ता ने प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तुरंत आवेदन नहीं किया और 9 सितंबर, 1987 को उद्देश्य के लिए एक आवेदन किया, जो 14 सितंबर, 1987 को प्राप्त किया गया था। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता प्रस्तुति से 9 दिन पहले बर्बाद हो गया था। प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन और चुनाव याचिका को भेजने के लिए उन्हें सात दिनों के लिए और आगे बर्बाद करने के बाद। डिप्टी कमिश्नर, इन परिस्थितियाँ में, प्रस्तुति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर एनेक्स्योर पी -3 द्वारा पारित अस्वीकृति का फैसला नियम 78 और 79 में उल्लंघन करता है- अस्मुच के रूप में डिप्टी कमिश्नर को राज्य सरकार को नियम 75 के तहत प्राप्त प्रत्येक चुनावी याचिका को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। मामला नियम 75 के उप-नियम (1) के प्रावधानों को कॉम नहीं दिया गया है, जो राज्य सरकार के साथ चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए एक आदेश पारित करेगा और इस तरह के आदेश को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहाँ यह शिकायत की जाती है कि चुनावी याचिका की याचिकाकर्ता की बेदिल की प्रस्तुति नियम 75 के उप-नियम (1) का उल्लंघन थी और डिप्टी कमिश्नर को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्तगी के लिए याचिका भेजने की आवश्यकता थी। हालांकि तर्क स्पष्ट रूप से अटैक्ट-टिव लगता है, लेकिन करीब से जांच करने पर तर्क के लिए खड़ा नहीं होता है। नियम 75 के उप-नियम (1) में तनाव सीमा की अवधि के भीतर याचिका की प्रस्तुति पर है। एक याचिका जो सीमा की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, वह उतनी ही अच्छी है जितनी कि एक याचिका के रूप में उपायुक्त के हाथों में नहीं है और यदि ऐसा है, तो राज्य सरकार के लिए वार्ड के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं है। यह केवल एक प्रस्तुत याचिका है, जिसमें नियम 75 के उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रकार के विवरण का अभाव है, जो कि किसी भी दुर्बलता के मामले में राज्य सरकार को भेजे जाने के लिए वारंट होगा। तात्कालिक मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ है। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने प्रस्तुति पर याचिकाकर्ता की याचिका का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया था। इन कारणों से, यह याचिका 1987 के CWP नंबर 7409 से भी जुड़ी हुई है, जो समान तथ्यों पर है, लिमाइन में खारिज कर दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा